सामयिक प्रपत्रक-६

भारत के विकास की कहानी : असमानता एवं निर्धनता में असंतुलन

मैं अब पूरे भारत की यात्रा कर चुका हूं। किन्तु हाय! बन्धुओं, अपने नेत्रों से जनसाधारण की दरिद्रता और घोर विपदा देखना सचमुच पीड़ादायी है। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया।

स्वामी विवेकानन्द

India Policy Foundation
भारत नीति प्रतिष्ठान

सामयिक प्रपत्रक-६

भारत के विकास की कहानी : असमानता एवं निर्धनता में असंतुलन

डा0 राहुल सिंह

India Policy Foundation
भारत नीति प्रतिष्ठान

No part of this publication can be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers.

Published by :
India Policy Foundation
D-51, Hauz Khas, New Delhi-110016 (India)
Tele: 011-26524018
Fax: 011-46089365
E-mail: indiapolicy@gmail.com
Website: www.indiapolicyfoundation.org

Edition:
First : April, 2014
ISBN : 978-81-925223-5-7
© India Policy Foundation

Price :
Rupees Fifty only (Rs. 50.00)

Printed at : I'M World-09312431409

सारांश

यदि हम विकास की बात करते हैं तो विकास, समावेश और पुनर्वितरण के बीच प्राथमिक अंतर स्वाभाविक रूप से एकआयामी आय मापदण्ड से अलग गुणात्मक होता है। अत्यन्त गरीबी और अत्यधिक असमानता की व्यापक प्रकृति के कारण हमारे देश में लाखों लोगों का जीवन दांव पर है, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के सन्दर्भ में पुनर्वितरण का बेहिचक चुनाव सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। विकास समावेशी विकास की गारंटी नहीं देता और समावेशी विकास, ऐसा अपरिहार्य नहीं है कि न्याय में परिवर्तित ही हो। पिछले दशक में मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में भारत की स्थिति विश्वव्यापी शर्मिंदगी का विषय बन गयी है। और हाँ, इस अवधि में तेजी से आर्थिक विकास के कारण इस संवृद्धि ने गम्भीर असमानता, सघन पूँजीवाद और भ्रष्टाचार को जन्म दिया। हाल के दिनों में भारत में गरीब लोगों की संख्या के संदर्भ में दावे पर दावे किये गये हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि राज्य ईमानदारी से निष्ठापूर्वक लोगों को सशक्त करने के बजाय गरीबी रेखा के औजार का प्रयोग करके पिछले पायदान पर खड़े लोगों की संख्या को निरन्तर कम करने में लगा हुआ है। घनत्व का प्रभाव (density effect) गरीबों की वास्तविक संख्या को तो छुपा सकता है पर गरीबी की वास्तविकता को नहीं। आय में असमानता भी बढ़ रही है, जो विषमता का सबसे स्पष्ट प्रकार है। जनसंख्या में उच्च स्तर के लोग पिछले एक दशक में अपनी आय बढ़ाने में सफल रहे हैं जबकि नीचे के लोगों के साथ ऐसा नहीं नजर आ रहा है। हाल के दिनों में प्रचुर खाद्यान्न उत्पादन एवं प्रबल भूख के सन्दर्भ में गरीबी एवं अमीरी के बीच की खाँई और अधिक गहरी हुई है। गरीबी को लेकर बहुत सारे विरोधाभास सामने आए हैं जैसे देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के बाद भी व्यापक भुखमरी की स्थिति का अनुभव किया गया है। विश्व भूख सूचकांक (GHI) में भारत की स्थिति उसके दावे कि भारत एक उभरती महाशक्ति है, पर गम्भीर कुठाराघात है। यह कटु यथार्थ यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है कि पाँच वर्ष तक की आयु से नीचे की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा कुपोषण का शिकार है एवं् सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से ग्रस्त है। भारत की यह स्थिति उप–सहारा देशों से भी बदतर है। अंततोगत्वा, प्रश्न जो सबसे अधिक कचोटता है वह यह है कि मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार के दोहरे संकट के बीच उसी समय मानव विकास की भयानक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिछले दशक में सत्तारूढ़ सरकार के इरादों की स्पष्टवादिता मे कमीं। यदि इस दोहरे संकट पर नजर डालें तो स्थिति और भी भयावह है।

विषय–सूची

1. विकास, समावेशन और पुनर्वितरण : प्राथमिकता का प्रश्न
2. अस्वस्थता की अभिव्यक्ति : गरीबी एवं असमानता
3. घटती हुई गरीबी का विचित्र मामलाः कृत्रिम मूल्यांकन की कला
4. समृद्धि के महल
5. भूखी जनता, मरते किसान एवं सड़ता अनाज
6. अनैतिक इरादे

I

विकास, समावेशन और पुनर्वितरण:

प्राथमिकता का प्रश्न

विकास की स्थिति में विरोधाभास को ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष एमिलिओ मेडिसिन के द्वारा 1971 में कहे गए शब्दों में सरलता से बताया जा सकता है, जो उनसे वहां आए गणमान्य प्रतिनिधियों ने देश की आर्थिक स्थिति के विषय में प्रश्न किया था। उसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि "अर्थव्यवस्था तो बेहतर स्थिति में है पर देश की जनता नहीं"। पिछले एक दशक में भारत के विकास के प्रतिमान में इसी प्रकार का रहस्यमय विरोधाभास परिलक्षित होता है। चूँकि इसी दौरान विभिन्न अच्छे कारणों के लिए भारत के तीव्र आर्थिक विकास की प्रशंसा की गई, लेकिन इस आर्थिक वृद्धि का समाज के सीमांत वर्ग पर सीमित प्रभाव चिंता का विषय है। पिछले छह दशकों में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के कपटपूर्ण वादे के पीछे का सच आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट हो जाता है जब "नियति के साथ साक्षात्कार"[1] की बात करके लाखों की संख्या में आम लोगों को नजरअंदाज किया जाता है।

यदि हम अधिक गम्भीरता से बात करें तो ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में निराशाजनक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को विकास दर के साथ चारो ओर तीव्र आर्थिक विकास पहले ही लुप्त होने लगा है। असमानता और गरीबी का करुण क्रन्दन ही स्थाई रूप से शेष बचा है।

अतः समावेशी होने का क्या मतलब है जब इसे हर दिन और बार–बार नीतियों के बाजार में बेंच दिया जाता है? विचार की केन्द्रीय भूमिका क्या है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह कैसे भिन्न है, जहाँ तीव्र प्रतिरोध और असमानता गहराई तक अपनी जड़े जमाए हुए हैं?

जैसा कि अली और झुआंग[2] द्वारा विश्लेषित किया गया है कि समावेशी विकास सरल एवं सामान्य काम नहीं है, बल्कि यह लोगों को सामाजिक विकास प्रक्रिया में सम्मिलित करता है और निष्पक्षता के आधार पर उत्पादों पर अधिकार को सुनिश्चित करता है, "विकास तभी समावेशी होता है जब वह समानता के आधार पर समाज के सभी सदस्यों को उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना विकास प्रक्रिया में सहभागिता एवं योगदान के लिये अनुमति देता है।" रेवेलियन और चेन[3] ने विकास को गरीब समर्थक के रूप में परिभाषित किया है, अगर यह गरीबी को कम करता है और समावेशी विकास में वृद्धि करता है। दूसरी तरफ इन्होंने संवृद्धि को परिभाषित किया है कि संवृद्धि वह है जो असमानता में वृद्धि से संबंधित नहीं है।

कंबर और रुनियर[4] ने संवृद्धि, गरीबोन्मुखी संवृद्धि, समावेशी संवृद्धि एवं समावेशी विकास में कुछ सूक्ष्म भेद बताया है। आर्थिक संवृद्धि की परिभाषा अधिक सरल, संक्षिप्त और सर्वस्वीकार्य है जो कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से जुड़ी हुई है, जबकि गरीबोन्मुखी संवृद्धि में विकास का अर्थ आय सम्बन्धी गरीबी में कमी को बताया गया है। इसी क्रम में हुई समावेशी संवृद्धि उस विकास का प्रतीक है जिसमें निचले स्तर पर आय में असमानता होती एवं जिसके अंतर्गत कम आय वाले लोगों की आय में बहुत ज्यादा असमानता होती है। अतः विकास गरीबोन्मुखी हो सकता है लेकिन यह जरूरी नहीं की वह उन तक पहुंच ही रहा हो। इसका मतलब यह है कि गरीबी उन्मूलन उससे जुड़ी हुई असमानता लाएगा। जबकि समावेशी विकास आय के कठिन मापदण्डों को तोड़ता है और एक व्यापक अवधारणा के अन्य मानदंडों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसरों में वृद्धि जैसे कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (Millennium Development Goal) आदि का लोगों की बेहतरी के लिए अपनाता है।

आर्थिक–संवृद्धि किसी देश के प्रदर्शन को मापने के लिये एक बहुआयामी माप है। हालाँकि गरीबोन्मुखी संवृद्धि, समावेशी संवृद्धि और समावेशी विकास बेहतर लोगों की बेहतरी को मापने के सूक्ष्मतम मापदण्ड हैं। सत्तारूढ़ दल के दावों को सत्यापित करने के लिए इसको परिभाषित करके जब विकास के सूचकों को खोजा जाता है तब इसका तात्पर्य रोजगार के अवसर, सामाजिक समावेश और सामाजिक सुरक्षा, साथ ही सुशासन और संस्थाओं के साथ आर्थिक विकास हो जाता है, जिस पर यह निर्भर करता है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 35 संकेतकों की एक सूची तैयार की है, जिसमें विशिष्ट समावेशी विकास सूचकों को जोड़ा गया है (1) गरीबी और असमानता (आय या बिना आय) (2) आर्थिक विकास और रोजगार (3) प्रमुख बुनियादी ढांचा निधि (4) शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच (5) आधारभूत ढांचागत उपयोगिताएँ और सेवाएं (6) लैंगिक समानता और अवसर (7) सामाजिक सुरक्षा जाल (8) सुशासन और संस्थाएं।[5]

योजना आयोग द्वारा बनाई गई 12वीं पंचवर्षीय योजना के भाग–1 का शीर्षक था 'तीव्र, और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास।' ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के भाग–1 का शीर्षक है 'समावेशी विकास'।

जिस आवृत्ति के साथ समावेशी, न्यायसंगत और स्थाई विकास जैसे शब्दों का प्रयोग ज्यादातर नीतिगत दस्तावेजों में हो रहा है, उसको देखकर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का इरादा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि योजना आयोग इन स्थायी एवं समावेशी विकास आदि शब्दों के अर्थ और इनको पूरा करने की नीतियों तथा साधनों से अनभिज्ञ है।[6] लेकिन अब तक अक्सर समावेशी विकास को नीतिगत दृष्टिकोण में स्पष्टता की कमी, भ्रम, अनिश्चितता, अनौपचारिकता के द्वारा चित्रित किया गया है न कि धारणीयता को ध्यान में रखकर। वैसे तो समानता सार्वभौम रूप से स्वीकृत मूल्य है और सामान्यतः मूलभूत मानवाधिकार माना जाता है लेकिन प्रश्न यह है कि किस बात की समानता? जैसा के अमर्त्य सेन अक्सर पूछते हैं। इस प्रश्न का उत्तर नीतियों को पहचान तथा उन्हें बढ़ाने के लिए और गरीबी उन्मूलन व समानता को सुनिश्चित कराने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होना ही था।[7]

---

1 http://www.svc.ac.in/files/TRYST%20WITH%20DESTINY.pdf
2 Ali and Jhuang, Inclusive Growth towards Prosperous Asia, 2007
3 Ravallion, Martin & Chen, Shaohua, 2003. "Measuring pro-poor growth," Economics Letters, Elsevier, vol. 78(1), pages 93-99, January
4 Kanbur, Ravi and Rauniyar, "Conceptualizing Inclusive Development: With Application to Rural Infrastructure and Development Assistance", June 2009
5 "Framework of Economic Growth Indicators: Key Indicator for Asia and the Pacific", 2011, Asian Development Bank
6 Is Sustainability Truly Built into the 12th Plan? — Ashish Kothari, Kalpavriksha Environment Action Group
7 Dr. Amartya Sen rightly points out the diversity of characteristics possessed by human beings (e g, age, gender, general abilities, inborn talents, proneness to disease, physical and mental capabilities) and external circumstances (such as ownership of assets, residential locations, social background and so on) so you cannot have equality for everything and policy space for remedial action has to be identified and acted upon

II अस्वस्थता की अभिव्यक्ति : गरीबी और असमानता

आर्थिक और न्यायसंगत विकास के बीच सहसम्बन्धों पर अक्सर प्रश्न किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि विकास किसी काम का नहीं है, अपितु यह प्राथमिक आवश्यकता है। लेकिन विकास को एक उपकरण के रूप में बदलकर इसे देश की मानवीय पूंजी के रूप में विकसित करना या मानवीय क्षमताओं का सार्वभौमिक विकास के लिए प्रयोग करना उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है जितना की सोचा जाता है। धीरे–धीरे विकास को समाज के निचले स्तर की ओर ले जाने वाला प्रसिद्ध सिद्धांत कम से कम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत कम सफल रहा है। पक्षपात और असमानता बढ़ी है और यह निचले स्तर तक अलग–अलग आर्थिक समूहों तक फैल गई है। आर्थिक सुधारों के बाद के समय में असमानता बढ़ने की गति प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से उच्च स्तर से निम्न स्तर तक की जनसंख्या में तेज हुई है।[8] लोगों के उत्थान का व्यापक आधार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रहा है जो कि प्रजातंत्र की बानगी है और इसका मूल्यांकन केवल सकल घरेलू उत्पाद से किया जा सकता।

आरेख 1: मानव विकास सूचकांक क्रम : भारत[9]

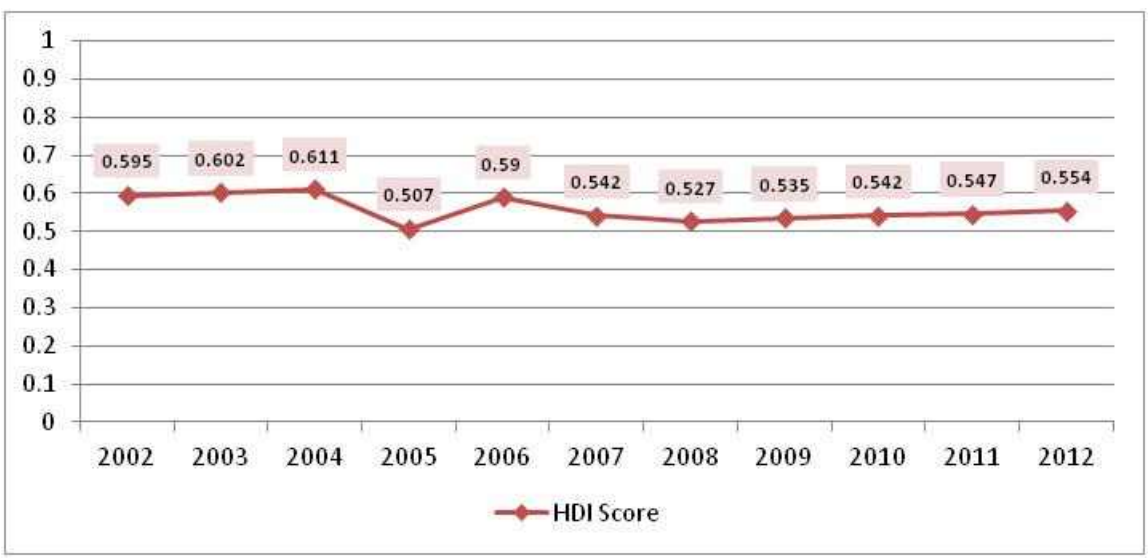

मानव विकास सूचकांक मानव के विकास को मापने का एक संयुक्त सूचकांक है, जिसमें इन तीन आयामों द्वारा विकास की उपलब्धियों का औसत मापा जाता है – दीर्घ और स्वस्थ जीवन, ज्ञान और बेहतर जीवनस्तर। ये तीनों आयाम जीवन की तीन प्रमुख शर्तें हैं जिन पर मानव विकास का विमर्श प्रारम्भ होता है और यह विकल्पों के प्रति जागरूक वृद्धि है जैसा कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब अल हक, जिन्हें एचडीआर का जनक कहा जाता है और नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने बताया है। जीवन स्तर को मापने के इस वैकल्पिक साधन में भारत को इस विकास के सूचकांक के सबसे निचले स्तर पर लगातार लम्बे समय से बढ़ते रहने का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2013 में जारी किए गए मानव विकास सूचकांक में भारत 187 देशों में 139वें स्थान पर था। इस तथ्य से हमारे देश में जो दावे और आत्मसमीक्षा की जाती रही है, उसे चुनौती देने में मदद मिलेगी। भारत के मानव विकास सूचकांक द्वारा भारत के विकास के स्तर के बारे में यह कम से कम एक चौकाने वाली सच्चाई है। (चित्र 2)

आरेख 2: मानव विकास सूचकांक क्रम तालिका: भारत[10]

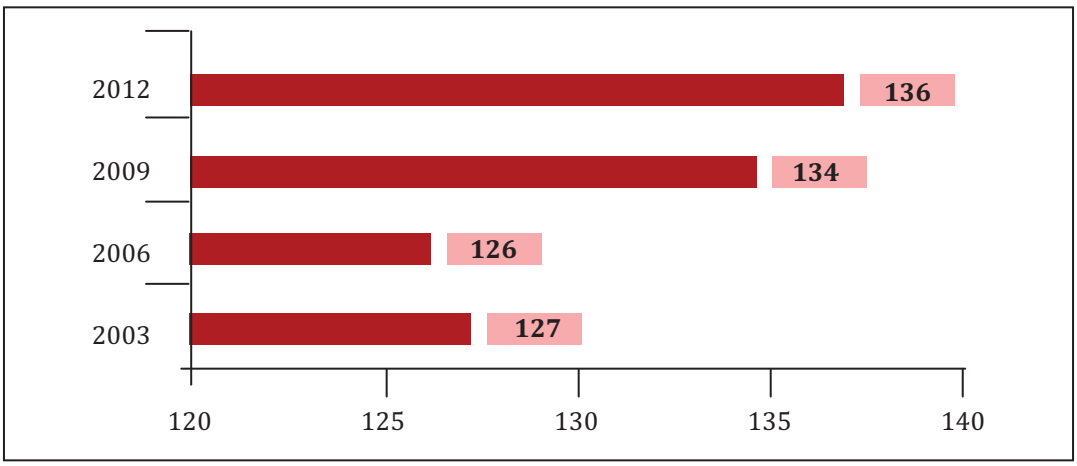

दिए गए आरेख से स्पष्ट है कि पिछले दशक के एचडीआई में भारत का परिणाम देखकर पता चलता है कि यह स्थिर था। लेकिन यदि इसे ध्यान से देखें तो पायेंगे कि यह नीचे खिसका है। ऐसा उस समय हुआ है जो समय भारत के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता रहा है। कुल 180 देशों के आर्थिक विकास मानदंडो के मध्य भारत लगातार नीचे के 50 देशों में परिगणित होता रहा है। पिछले 9 वर्षों (2003 से 2012 के बीच) में एचडीआर का स्टार 9 अंक तक नीचे गया है। जब हम भारत की इस दयनीय मानव विकास रिकॉर्ड और जीडीपी के विकास की प्रवृत्ति को देखते हैं तब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि यह इतनी बड़ी असफलता के दौरान अनुपयुक्त पूंजी वितरण के कारण बढ़ी हुई असमानता का परिणाम है। न केवल अन्यायपूर्ण आर्थिक विकास अपितु महँगाई के चाबुक ने भी निचले स्तर के लोगों को बहुत कष्ट पहुँचाया है। आवश्यक वस्तुओं में मूल्यवृद्धि ने लोगों की स्थिति को और कमजोर किया है क्योंकि इसका प्रभाव सामान्य लोगों की उपभोग क्षमता पर पड़ा है। ज्यादातर मामलो में इन लोगों को पोषण संबंधित मसलो पर समझौता करना पड़ा है क्योंकि सामान्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम लगातार बढे हैं जैसे कि दालें, दूध, अंडे और

मांस। इन सब के बढ़े दामों ने जीवनयापन महंगा कर दिया है और लोगों पर अभाव और गरीबी पर उल्टा प्रभाव डाला है।[11] (आरेख–3)

आरेख 3 : जीडीपी संवृद्धि दर और महंगाई[12]

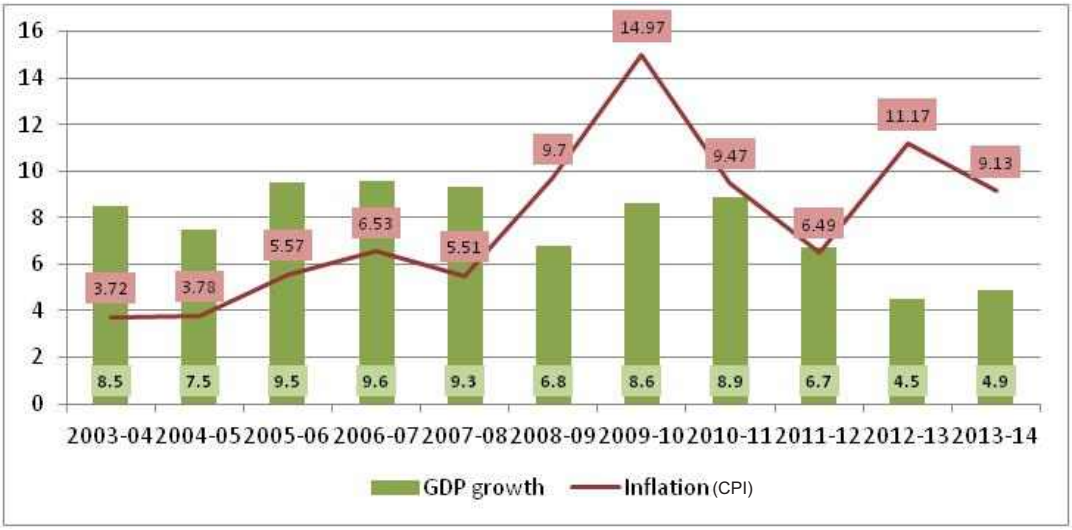

अब आर्थिक मंदी के साथ–साथ नौकरियों की दयनीय स्थिति (नई नौकरियों को लेकर और नौकरी की सुरक्षा को लेकर) और स्थिर मेहनताना ने लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। यदि हम भारतीय अर्थव्यस्था की बात करें तो इसका लगभग आधा (55 प्रतिशत) 185 ट्रिलियन डॉलर अनौपचारिक है। केवल उप–सहारा अफ्रीका में भारत की अपेक्षा सबसे बड़ी असंगठित अर्थव्यस्था है। भारत में अनौपचारिक रूप से खेतों में काम करने वाले 84 प्रतिशत हैं।[13]

---

8 Majumdar, Rajshi, "Growth and Development: The Indian Experience" 2005

9 Human Development Reports, 2002 to 2012, accessible at http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IND

10 Ibid

11 http://www.thehindu.com/opinion/Readers-Editor/battling-food-inflation-state-people-and-media/article106619.ece

12 Central Statistical Organisation(CSO) Estimates
http://www.inflation.eu/inflation-rates/india/historic-inflation/cpi-inflation-india-2013.aspx
http://www.livemint.com/Politics/p1HXxTk6vMf3A4a3oZ1p0O/India-slightly-lowers-FY14-growth-forecast-to-49.html

13 http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-10-25/news/43395491_1_neelkanth-mishra-india-fall-informal-economy

III घटती हुई गरीबी का विचित्र मामला : कृत्रिम मूल्यांकन की कला

उच्चतम न्यायालय के एक उत्तर में प्रथम शपथ–पत्र के माध्यम से योजना आयोग ने 10 मई, 2011 को बताया कि क्या योजना आयोग ने पात्र लाभार्थियों के 37.2 प्रतिशत समान रूप से निर्धारित उच्चतम सीमा को लागू किया है? योजना आयोग ने जवाब देते हुए बताया की उच्चतम सीमा निर्धारण की आवश्यकता गैर सार्वभौमिक लाभ प्रणाली के लिए आवश्यक है। बाद में न्यायालय ने इस पर थोड़ी आशंका इसकी 2004–05 की गणना को लेकर जताई और एक निर्देश दिया की मई 2011 को मूल्य सूचकांक के आधार पर यह प्रति व्यक्ति गणना मानदंड में परिवर्तन कर सकता है।[14] (उच्चतम न्यायलय के निर्देशानुसार, योजना आयोग ने अपने 20 सितम्बर को दूसरे शपथ पत्र में गरीबी रेखा को 965 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति महीने के हिसाब से 32 रूपए प्रतिदिन माना जबकि ग्रामीण इलाको में 781 रूपए प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के हिसाब से 26 रूपये प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया और इसके लिए जून 2011 के मूल्यों को विचार के लिए रखा गया।[15]

इनकी उपयुक्तता तब उभरकर सामने आई जब इन्हें परिवार के बजट के परिप्रेक्ष्य में देखा गया जो कि 4824 रूपए प्रति परिवार प्रति महीना शहरों में जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 3905 रूपए होता है। इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है, ऐसे परिवारों को सम्मिलित करके, जो सामाजिक सहायता के हकदार हैं। यह गरीबी का अल्प और छोटा दायरा तेजी से बढ़ते हुए खाद्य पदार्थों के मूल्यों के मद्देनजर संवेदनशीलता के स्तर पर एक गलत टिप्पणी है और उच्च नीति निर्धारकों के बीच चिंता का विषय है। यह इस बात को भी दर्शाता है कि योजना आयोग जैसे भारी भरकम संस्थान जमीनी सच्चाई से किस तरह से दूर हो गए हैं। इस मसले से एक और बात सामने आती है कि राजनीतिक लोगों का एक धड़ा किस तरह से जबरदस्त अज्ञानता से जूझ रहा है और वह इन विषयों पर किस तरह का दृष्टिकोण रखता है? इन राजनेताओं में से राज बब्बर और रशीद मसूद ने तो संवेदनहीन जुमले भी खाद्य पदार्थ की कीमतों पर गढ़ डाले।

राज बब्बर ने कहा कि "आज भी मुंबई शहर में मैं 12 रूपये में भरपेट खाना खा सकता हूँ। केवल वड़ा पाव ही नहीं बल्कि काफी सारा चावल, दाल, सांभर और कुछ सब्जियां भी इसमें होगीं।" जब राज बब्बर ने कहा की एक बढ़िया भोजन 12 रूपये में मिल सकता है तो एक और कांग्रेसी नेता रशीद मसूद ने कहा कि 5 रूपये भी दिल्ली में काफी है पेट भर के खाने के लिए। मसूद ने कहा कि आप दिल्ली में 5 रूपये में पूरा खाना खा सकते हैं हालांकि मै मुंबई के बारे में नहीं जानता।

इन दोनों कांग्रेस के बड़े नेताओ की टिप्पणियों के कारण लोगों में रोष व्याप्त हो गया और लोगों ने इस मसले को लेकर काफी शोर मचाया तथा सब जगह इस बात की घोर आलोचना हुई। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं था। केंद्रीय मंत्री फारूख अब्दुल्लाह भी इस बहस में कूद पड़े और कहा कि "आप 1 रूपये में भी पेट भर सकते हैं और 100 रूपये भी कम हैं पेट भरने के लिए। प्रश्न यह है कि आप क्या खाना चाहते हैं? हम चाहते है की देश का विकास हो। ये सारी चीजें देश को आगे ले जाएंगी।"[17]

इस कहानी का अगला मोड़ तब आया जब इस कठिन गरीबी जैसे संजीदा मसले को योजना आयोग द्वारा ही कमतर आँका गया। जुलाई 2013 में जो आंकड़ा योजना आयोग द्वारा जारी किया गया उसने दावा किया कि देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या घटकर अब 2011–2012 में 22 प्रतिशत ही रह गई है जबकि यह 2004–05 में लगभग 37 प्रतिशत थी। परम्परागत रूप से गरीबी को भारत में आधिकारिक रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के गणना–अनुपात के रूप में गरीबी का आकलन करने के लिये योजना आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा खाद्य और अन्य वस्तुओं के उपभोग पर विचार करके बताई गई प्रविधि द्वारा मापा जाता है। इस तरीके से भारत की गरीबी के आकड़ो को सामने लाया जाता है और हर पांच वर्ष में यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। इस समिति ने ही 2004–05 का गरीबी का स्तर निर्धारित किया था। जबकि बाद के वर्षों का गरीबी का निर्धारण भी इसी तरीके से किया गया था लेकिन इसमें कीमतों में वृद्धि को मूल्यों के साथ समायोजित कर दिया गया था। (आरेख 4)

लेकिन क्या गरीबी उतनी ही तेजी से गायब हुई है जितनी तेजी से योजना आयोग दावा कर रही है या यह सब कुछ एक बेहतर ऊपरी दिखावा मात्र है? क्या सच में 2004–05 के दौरान 138 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं, जैसा की योजना आयोग दवा कर रहा है?

आरेख 4 : राष्ट्रीय गरीबी अनुमान (गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत) (1993'–2012)[18]

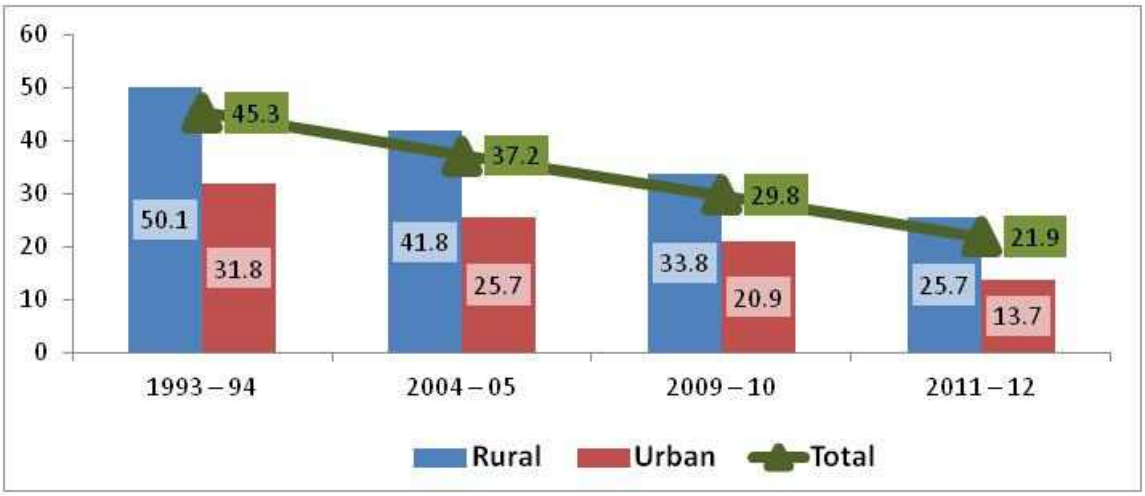

डॉ अमर्त्य सेन और डॉ जीन ड्रॉज ने अपनी किताब 'एन अनसर्टेन ग्लोरी : इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शन' में गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की घटी संख्या का रहस्योद्घाटन करने का प्रयास किया है। जिसके लिए वे घनत्व प्रभाव को जिम्मेदार मानते हैं : वास्तविक स्थिति यह है कि बहुत से लोग गरीबी रेखा से थोड़ा सा ही नीचे हैं अतः यदि प्रति व्यक्ति खर्च को थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो ये सारे लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ जायेंगे और तब घनत्व प्रभाव से ऐसा नजर आएगा कि आधिकारिक तौर पर गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या बहुत कम है। वास्तव में गरीबों का कम होना एक ऐसा विषय रहा है जिसने भारत में लगातार विवाद पैदा किए हैं वह भी बहुत जोरदार ढंग से। ज्यादातर चर्चा इस बात पर रही है कि गरीबी रेखा के नीचे कौन लोग हैं? न कि गरीब पर ध्यान दिया गया है। इस दौरान एकमत और सहमति कभी नहीं बन पाई की गरीबी रेखा के नीचे कौन हैं और यह संदेह बना रहा की गरीब कौन हैं?

अर्जुन सेनगुप्ता समिति जिसका गठन केंद्र सरकार के अति लघु, लघु और मझोले उद्योग मंत्रालय ने किया था एवं जिसका उद्देश्य था कि यह समिति असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों की समस्याओं का समाधान बताएगी। उसने इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की संख्या निर्धारित करने में सफलता पाई है कि कितने लोग असंगठित क्षेत्र में हैं और कितने लोग अनौपचारिक मजदूर हैं? यह संख्या कुल कार्य क्षमता के लगभग 92 प्रतिशत है जिनके पास न तो रोजगार की सुरक्षा है और न ही काम की सुरक्षा और न ही सामाजिक सुरक्षा। यदि अनुभवजन्य मानकों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस तरह के कामगारों के बीच उच्च स्तर की एकरूपता है, देश के 77 प्रतिशत जनसंख्या के बीच। 2004–05 में जिसका प्रतिदिन का उपभोग 20 रूपये प्रतिदिन हैं, ऐसे लोग गरीब और कमजोर कहलाते हैं ।

इस वर्ग में पाए जाने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जो 1999 में 00–81.1 करोड़ से बढ़कर 2004–05 में बढ़कर 83.6 करोड़ हो गई। इस रिपोर्ट ने अनौपचारिक मजदूरो के सम्बन्ध में विकासशील अर्थव्यस्था पर बहुत तीखा प्रहार किया है। "पिछली शताब्दी के समाप्त होने तक अर्थव्यस्था में इस तरह के उछाल ने एक उत्साह का संचार किया है हालाँकि ज्यादातर लोग जिनके पास एक दिन में उपभोग के लिये 20 रूपये भी नहीं थे उन पर इसका कोई असर नहीं था। लगभग ७६ प्रतिशत अनौपचारिक और असंगठित मजदूर इस अनुभाग से सम्बन्ध रखते हैं। उनकी नौकरियों के लिए बिना किसी कानूनी सुरक्षा या उनके काम करने के हालत या सामाजिक सुरक्षा के और नितांत गरीबी में रहते हुए शाइनिंग इंडिया के गौरव से वंचित है।"[19]

डॉ एन. सी. सक्सेना समिति का गठन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबीरेखा से रहने वालों की जनगणना कैसे की जाय, इसपर उपयुक्त सलाह देने के लिये किया था न कि गरीबीरेखा के आकलन के लिए। हालांकि विशेषज्ञ मंडल ने रिपोर्ट 21 अगस्त, 2009 को सौंप दी थी। जिसमें यह कहा गया था कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत में 50 प्रतिशत तक ऊपर की ओर बदलाव संभव है।[20] इस आकलन के साथ एन. सी. सक्सेना ने कहा कि यह गरीबी की संकुचित परिभाषा, जिसका अब तक हम प्रयोग करते रहे हैं। जिसे अब तक हम कुत्ता–बिल्ली की रेखा कहते रहे हैं, क्योंकि इससे सिर्फ कुत्ता और बिल्ली जीवित रह सकते हैं।'[21]

आरेख 5: गरीबी का प्रतिव्यक्ति अनुपात 1.25 डॉलर प्रतिदिन (PPP)
(जनसंख्या का प्रतिशत)[22]

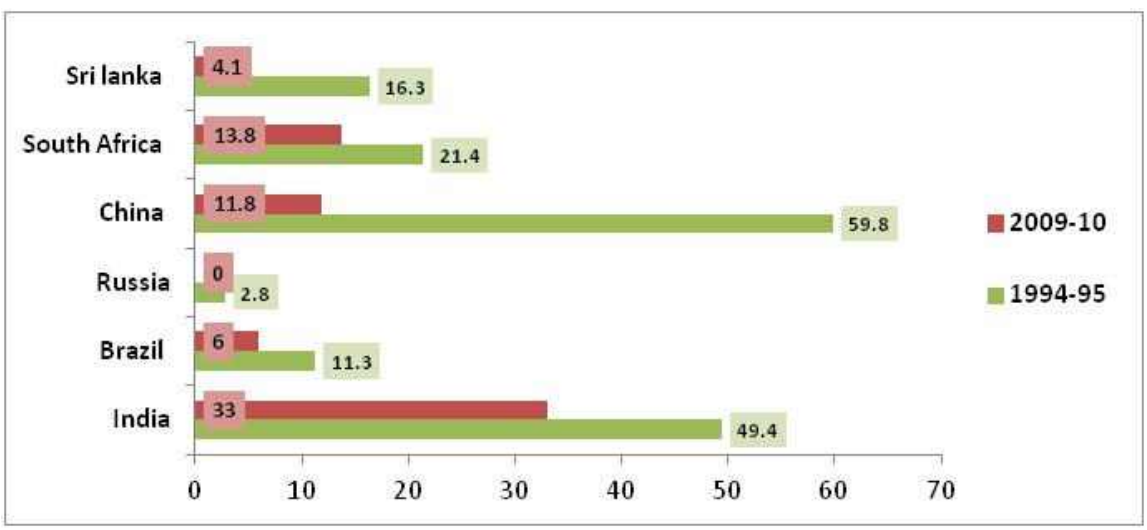

लेकिन अब जो मुख्य प्रश्न दिमाग में आता है कि भारत क्यों गरीबी की रेखा के नीचे के दायरे के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक 1.25 डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता? बल्कि इसके उल्टा यह आँकड़े की हेराफेरी और लम्बी चौड़ी बातों से लगातार अपने आप को एक उबारता हुआ सर्वोच्च शक्ति (सुपर पावर) दिखने की कोशिश करता है। लेकिन वास्तविक समस्या है कि 32 रूपये प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति शहर के और 26 रूपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति गांव के लोगों की आय होने के बावजूद 26.97 करोड़ लोग अब भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते है।

ये लोग किस तरह जीवनयापन करेंगे? यह भयानक लेकिन छिपी हुई गरीबी, इन गरीब लोगों के सम्मान का प्रश्न, भयावह करने वाला जीवन स्तर जो इन्हें सहन करना पड़ता है, हर दिन जिंदगी जीने के जद्दोजहद और कई तरह का अभाव जो इन्हें झेलना पड़ता है वह नीति निर्धारकों और मीडिया के लोगों को बमुश्किल नजर आता है।

जब इसे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो पिछले 15 वर्ष में भारत का प्रदर्शन पूर्ण गरीबी से लोगों को बाहर निकाल रहे ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के किसी अन्य सदस्य देश की तुलना में बहुत खराब रहा है। दिए गए टेबल से स्पष्ट है कि चीन ने किस तरह अपने देश में ऐसे लोगों की संख्या जो कि 1.25 डॉलर प्रतिदिन के काम कमाते है। 59.8 प्रतिशत से 11.8 प्रतिशत तक घटाने में सफलता पाई है, जबकि भारत 70 के दशक में लगातार गरीबी हटाओ[23] (23) की रट तो लगाता रहा है, लेकिन देश के लोगों को सामाजिक न्याय देने में बुरी तरह से असफल रहा है। दक्षिण एशिया के देशों में श्रीलंका ने आतंरिक आन्तरिक विवादों एवं कलह में उलझे रहने के बावजूद बाकी देशों से बेहतर किया है।

---

14 http://planningcommission.nic.in/aboutus/speech/spemsa/pr_dch0309.pdf
15 http://www.downtoearth.org.in/content/planning-commission-sc-rs-26-person-day-adequate-poverty-line
16 http://archive.indianexpress.com/news/after-raj-babbar-row-another-congressman-says-can-have-meal-in-delhi-for-less-than-rs-5/1146682/
17 http://ibnlive.in.com/news/re-1-enough-to-fill-your-stomach-it-depends-on-what-you-eat-says-farooq/409486-37-64.html
18 Press Note on Poverty Estimates, 2011 – 12, Planning Commission
19 Report of the Expert Group to Review the Methodology for Estimation of Poverty (2009) Planning Commission
20 " Report of the Expert Group to Advise the Ministry of Rural Development on the Methodology for conducting Below Poverty Line Census for 11th Five Year Plan, August 2009", Chairman N C Saxena
21 http://www.thehindu.com/news/national/beyond-the-debate-govt-accepts-65-indians-are-poor/article4948698.ece
22 The World Bank (http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY/countries?page=3)
23 https://www.google.co.in/search?q=garibi+hatao&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=b8EFU8jvEazW8gf374CIDQ

IV समृद्धि के महल

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री साइमन कुज्नेत्स ने 1955 में एक विचार दिया था। उनके अनुसार आय के बंटवारे में जो असमानता नजर आती है एवं जो गैर मोनोटोनिक प्रवृत्ति आर्थिक विकास की प्रक्रिया के साथ दिखाई पड़ती है : इस प्रवृत्ति का विस्तार समाज के संक्रमण के काल में औद्योगीकरण से पूर्व एवं औद्योगीकरण तक दिखाई पड़ता है। कुछ समय के लिए यह जैसे–जैसे और परिपक्व स्तर तक पहुंचा है वैसे–वैसे स्थिर रहा है और संकुचित हुआ है।[24] इस प्रकार से देश के विकास के मार्ग में आय के बंटवारे को कुज्नेत्स वक्र के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति आय और व्यक्तिगत आय असमानता के बीच एक उलटे यू (u) के आकार जैसा संबंध होता है। यह बलपूर्वक कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं किया जा सकता, जहां आय की असमानता आर्थिक विकास के साथ स्पष्ट हो जाती है।

भारत में असमानता की माप आय के द्वारा नहीं की जाती बल्कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा गणना किए गण्ये उपभोग–खर्च से की जाती है। इस आय–असमानता ने सामान्य आय असमानता को बढ़ाया है। भारत में पिछले दो दशक में तेजी से आय–असमानता बढ़ी है – भारत का गिनी गुणांक, जो कि किसी देश में असमानता का सरकारी मापक है, 0.32 से 0.38 हो गया है जबकि 0 आदर्श स्थिति है और 1 सबसे खराब स्थिति।[25]

लेकिन सबसे अधिक चिंताजनक प्रवृत्ति गांव में बढ़ती हुई असमानता है ––जिसका गुणांक 2011–12 में बढ़कर 0.280 हो गया है, जो कि 2004–05 में 0.267 था और अब तक के इतिहास में नगरों में सर्वाधिक 0. 37 एवं गांवों में 0.35 हो गया। 1993–94 में गिनी गुणांक 0.28 पहुंच गया, इसमें 1977–78 के बाद हुई पहली बार वृद्धि हुई थी, जब यह 1973–74 के 0.27 से बढ़कर 1977–78 के 0.34 तक 0.27 पहुंच गया था।[26] (आरेख 6)

आरेख 6 : उपभोग के वितरण का गिनी सूचकांकरू 1993–94 से 2009–10[27]

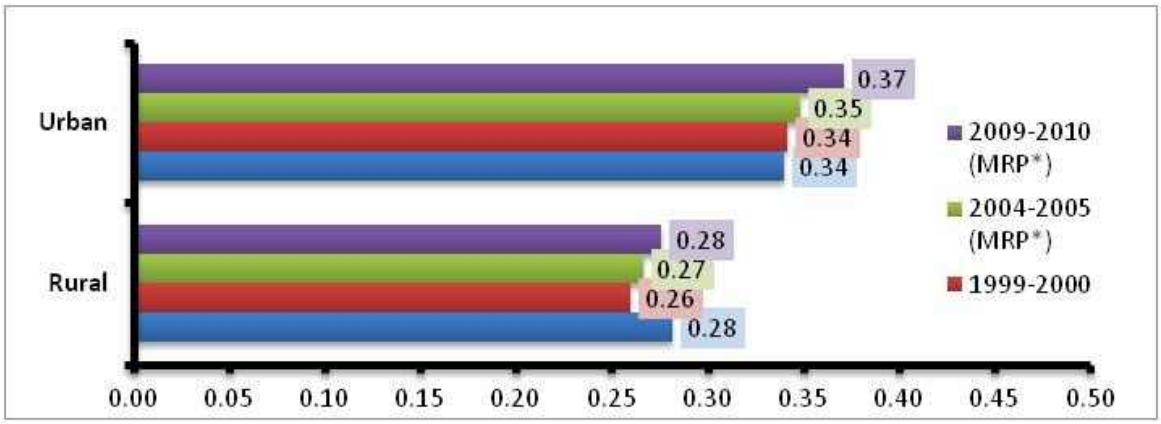

ग्राफ से स्पष्ट हो जाता है की पिछले डेढ़ दशक में घटने की बजाय असमानता मजबूत हुई है और बढ़ी है। नीचे से 10 प्रतिशत लोगों का विकास में हिस्सा 1994 में 4 प्रतिशत से घटकर 2010 में 3.7 प्रतिशत हो गया जबकि ऊपर के 10 प्रतिशत लोगों की आय में में बढ़ोत्तरी हुई है।

आरेख 7: आय में सहभागिता का प्रतिशत[28]

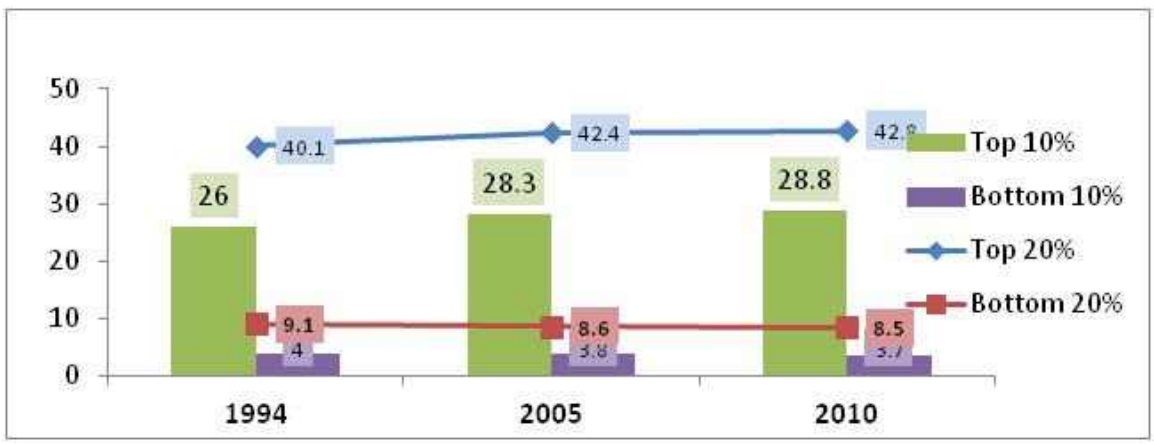

निराशाजनक प्रवृत्ति का परीक्षण नीचे के 20 प्रतिशत गरीब लोगों एवं ऊपर के 20 प्रतिशत धनी लोगों की संपत्ति के आधार पर किया जाता है। यह आधार पूर्णतः ऊपर से नीचे तक धन के प्रवाह के सिद्धांत को ही नकार देता है और आय की स्पष्ट असामनता को प्रमाणित करता है।

यदि हम पिछले 30 वर्षों का प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपभोग खर्च आंकड़े पर NSSO के सर्वे की ध्यान पूर्वक विवेचना करें तो हमें उपभोग–क्षमता में भारी असमानता नजर आएगी। देश के 20 प्रतिशत सर्वाधिक गरीब लोगों की प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह उपभोग–खर्च में भागीदारी गाँवों में 1993–94 में 9.6 प्रतिशत से घटकर 2004–05 में 9.5 हो गई है (इसके लिए उपभोग की गणना जनसंख्या के पांचवें भाग, जो कि सबसे गरीब है, का उपयोग किया जाता है) जिसके लिए यूनिफार्म रेफरन्स पीरियड पर आधारित URP तरीके का प्रयोग किया गया था, NSS में 2009–10 में इसके (मॉडिफाइड रेफेरेंस पीरियड – एमआरपी विधि से) थोड़ा बढ़े हुआ स्तर का पता लगा जो कि 9.8 था। शहरी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत सबसे ज्यादा गरीबों की हिस्सेदारी 1993–94, में 8 प्रतिशत से घटकर 2004–05 में 7.3 प्रतिशत और 2009–10 में 7.1 प्रतिशत हो गई।

यह जो उपभोग–खर्च की हिस्सेदारी में पिछले पांच वर्षों में जो कमी आई है वह बढ़ती हुई असमानता का सूचक है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। यहाँ इस निर्णय पर पंहुचा जा सकता है कि 1993–94 से लेकर 2009–10 के बीच जबकि अर्थव्यवस्था अपने उछाल पर थी, नीचे के 20 प्रतिशत लोगों का औसत उपभोग पर खर्च या तो स्थिर रहा है या बहुत ही कम बढ़ा है, जबकि ऊपर के 20 प्रतिशत लोगों का उपभोग इस समय के दौरान 20 प्रतिशत बढ़ गया। ग्रामीण भारत में उपभोग खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यह पहले जैसा ही रहा है, इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में आय का अंतर और उपभोग ऊपर के 10 प्रतिशत धनी लोगों और नीचे के 10 प्रतिशत गरीबों के बीच तेजी से बढ़ा है।[30]

तालिका 1

राष्ट्रीय उपभोग में गरीबों की सहभागिता[29]

	1993-94 (URP)	2004-05 (URP)	2009-10 (MRP)
ग्रामीण	9.6	9.5	9.8
शहरी	8	7.3	7.1

असमान आय–वितरण के स्तर को हाल में अधिक संपत्ति के सीमा को ऐसे लोगों के (जिनके पास 30 मिलियन डॉलर की कुल पूंजी है) अल्ट्रा हाई वर्थ (UNHW) पर जारी की गई (WEALTH-X) रिपोर्ट से जाना जा सकता है। यह भारत की वास्तविक आय–असमानता को प्रस्तुत करता है क्योंकि भारत में UNHW की संख्या 7850 है, जिसकी सम्मिलित पूँजी 935 बिलियन डॉलर है जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आधा है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या 103 है जिनकी कुल संपत्ति 1 बिलियन डॉलर है, जो कुल मिलाकर 180 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। इस संपत्ति का क्षेत्रीय वितरण भी बहुत असमान है क्योंकि 50 प्रतिशत UNHE वाले लोग बड़े शहरों दिल्ली और मुंबई आदि में रहते हैं और 90 प्रतिशत से अधिक अन्य 10 बड़े शहरों में।

जहां तक शहरी और ग्रामीण संपत्ति वितरण की बात है तो[31] अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लगार्डे ने कहा है कि भारतीय करोड़पतियों की कुल पूंजी में पिछले 15 वर्ष में 12 गुनी वृद्धि हुई है जो कि भारत की निरपेक्ष गरीबी को दो बार समाप्त करने के लिए पर्याप्त थी, जहाँ पर आय की असमानता भी तेजी से बढ़ रही है।'[32]

---

24 Kuznets (1955) formulates his proposition using available data from the industrialization period for the United States, England and Germany
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/~elsas/On%20Growth%20and%20Income%20distribution-final%20version.pdf

25 SAARC development Goals, India Country Report, August 2013, p 38

26 http://www.business-standard.com/article/economy-policy/rich-poor-gap-widens-in-india-113081000072_1.html

27 *MRP - Mixed Reference Period
[Source : Estimates of Planning Commission; NSSO 61st Round 2004-05, 66th Round 2009-10]
http://planningcommission.nic.in/data/datatable/ S no 49
Note: Gini coefficient is calculated assuming that all individuals within each state have gross income equal to per capita GSDP.

28 The World Bank accessible at (http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY/countries?page=3)

29 NSS report 538: Level and Pattern of Consumer Expenditure, Alternatively accessible at Millennium Development Goals, India Country Report 2014, Social, Statistics Division, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India

30 http://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/c-p-chandrasekhar/consumption-inequality-in-india/article3569657.ece

31 WEALTH-X : Connecting you to Wealth
http://www.wealthx.com/wealthxubswealthreport/

32 http://www.deccanchronicle.com/140204/news-businesstech/article/income-inequality-rise-countries-india-imf

V भूखे लोग, मरते किसान और सड़ता अनाज

भारत की भूख, आभाव और अल्पपोषण की ह्रदय विदारक कथा सभी महाद्वीपों में फैली हुई है। यदि हम लोगों की पीड़ा को नजदीकी से अध्ययन करें तो उनकी मूकवेदना की कहानी बहुत कष्टप्रद लगती है। भारत ने पिछले 200 वर्षों में अनगिनत अकाल देखे हैं। इनमे से कुछ के परिमाण इतने भयानक थे जिसकी अबतक मानवीय पीड़ा की दृष्टि से किसी अन्य से कोई तुलना नहीं की जा सकती जैसे कि 1943 का बंगाल का अकाल जिसमें अकथनीय मानवीय त्रासदी ने 60–70 लाख लोगों को निगल लिया था।[33] हाल के दिनों में हालांकि अकाल तो नहीं पड़ता लेकिन लोगों की मौत और जानमाल का नुकसान लगातार हो रहा है और इसका क्षेत्र काफी विस्तृत है। अधिकतर मामले न लोगों की दृष्टि में आते हैं न मीडिया द्वारा प्रकाश में लाए जाते हैं। 1970 के दशक तक खाद्य पदार्थो की गंभीर कमी के कारण अधिकतर मृत्यु भूख के कारण होती थी। परंतु हरित क्रांति ने भारत खाद्यान्न आयातित करने वाला देश है, इस कलंक से देश को मुक्ति दिलाई।

बाद के वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है जो कि स्वतंत्रता के समय 50 मिलियन टन से बढ़कर 1996–97 में 198 में 198 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक हो गया था[34] और यह 2012–13 में बढ़कर 263.20 मिलियन मीट्रिक टन हो गया।[35] देश में खाद्यान्नों की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद भारत तेजी से उभरते हुए देशों के बीच बहुत पीछे चल रहा और इसे वैश्विक भूख सूचकांक श्रेणी में 78 देशों के बीच 63 वें स्थान प्राप्त हुआ। वैश्विक भूख सूचकांक (GHI)[36] की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान किया था जो विश्व भर में भूख पर नजर रखता है और इसकी माप करता है तथा इसके लिए तीन सूचकांकों का प्रयोग करता है पहला अल्पपोषण, दूसरा शिशु का कम वजन और शिशु–मृत्यु दर।[37]

यह बहुत कष्ट की बात है कि भारत का प्रदर्शन सभी सूचकांकों के दृष्टि से बहुत ही दुखद है। यह इस बात को दर्शाता है कि एशिया के 19 देश अभी भी भुखमरी के शिकार हैं। भारत एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो चेतावनी के स्तर तक भुखमरी की गिरफ्त में है। भारत और तिमोर लेस्ते ऐसे दो देश हैं जहाँ 5 वर्ष की आयु से कम 40 प्रतिशत बच्चों का वजन कम है और वे भूखमरी से ग्रस्त हैं।[38]

यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण के मामले में भारत की स्थिति उप–सहारा देशों से भी ज्यादा दयनीय है। विश्व के हर तीन कुपोषित बच्चों में से एक भारतीय है, जिसमें से 47 प्रतिशत कम वजन वाले हैं और इसमें से 16 प्रतिशत किसी कार्य योग्य नहीं रह जाते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये सारे के सारे बच्चे भयानक रूप से कुपोषित हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित हुआ है कि कुपोषण बच्चों का संज्ञानात्मक, भौतिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास रोकता है और यूनिसेफ के एक आकलन के हिसाब से भारत में 50 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु कुपोषण से होती है।

इससे भिन्न 74 प्रतिशत 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 90 प्रतिशत किशोर लड़कियां तथा 50 प्रतिशत महिलायें रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। एनीमिया जिसका विकास पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव होता है तथा वह बच्चों का विकास और मासूम बच्चों की जान भी खतरे में डालता है।[39]

कुपोषण की यह अत्यन्त चिन्ताजनक एवं कष्टप्रद प्रवृत्ति नन्दी फाउन्डेशन द्वारा प्रस्तुत भूख और कुपोषण रिपोर्ट (HUNGAMA) में भी दर्शाई गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 5 वर्ष से कम आयु के 42 प्रतिशत बच्चे अत्यधिक या सामान्य कम वजन के हैं और 59 प्रतिशत इस प्रकार के बच्चे हैं, जो औसत लम्बाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वे स्टंटिंग से पीड़ित हैं। ऐसा भी पाया गया है कि इस प्रकार के बच्चों में से आधे इस बीमारी से अत्यधिक पीड़ित हैं तथा उनका वजन कम है अथवा प्रारम्भिक वे दो वर्षों तक इस बीमारी से पीड़ित होते हैं।[40] दुर्भाग्य से इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री ने जारी किया था जिन्होंने भुखमरी को राष्ट्रीय शर्म कहा था लेकिन इस विषय पर कोई सार्थक प्रयास अब तक नहीं किया गया।

तालिका 2: जीएचआई के विभिन्न सूचकांकों में भारत की स्थिति[41]

	Proportion of undernourished in the population (%)	Prevalence of undernoorishment in children under 5 years (%)	Under 5 mortality rate
1990-92	26.9	59.5	11.4
1994-96	25.2	45.9	10.1
1999-01	21.3	44.4	8.8
2004-06	20.9	43.5	7.5
2010-12	17.5	40.2	6.1

अतः इससे यह विरोधाभास पता चलता है कि हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं अपितु वितरण की समस्या एक प्रमुख चुनौती है। यह चुनौती खाद्य–वितरण से जुड़ी हुई है तथा इसमे हमारा देश पूरी तरह असफल हुआ है। इस सबके बावजूद भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बहुत ही प्रभावी ढंग से छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में लागू किया गया है जिसने ये अद्भुद कारनामा करके दिखा दिया है कि इसमें शून्य हानि की सम्भावना है[42] और लगभग सभी लोगों को कम मूल्य में खाद्यान्न वितरित करने की क्षमता है जो कि शासन में संरचनात्मक और कानूनी परिवर्तन लाकर सरलतापूर्वक किया जा सकता है।

आरेख 8 : प्रतिव्यक्ति पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रवृत्ति[44]

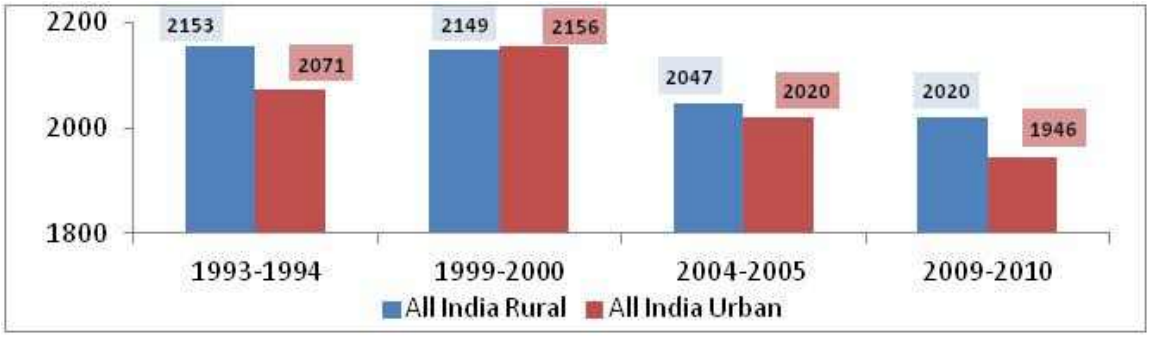

पोषक तत्वों को ग्रहण करने के सन्दर्भ में भारत के शहरों एवं गाँवों की दुखद वास्तविकता NSSO के सर्वेक्षण में वर्णित है, जिसमें प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहण की घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार यदि हम 1993–94 से इसकी तुलना करें तो 2004–5 से 2009 के मध्य ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति कैलोरी ग्रहण करने में 6 प्रतिशत की कमी आई है।

यह अत्यंत प्राथमिकता का प्रश्न है क्योंकि हमारे देश में भोजन देश की प्रमुख राष्ट्रीय आवश्यकता की सूची में कभी नहीं था। देश में जब उत्पादन बढ़ा तब भी सरकार ने वितरण और भंडारण को नजरअंदाज किया। बिना किसी योजना के बड़े पैमाने पर खरीददारी ने वस्तुओं को और बर्बाद किया है– जैसे अनाज खुले में सड़ रहा है और लाखो लोग भूखे पेट सो रहे हैं।

सूचना–अधिकार के तहत एक प्रश्न उत्तर में यह बात प्रकाश में आई कि कम से कम 17546 टन अनाज 2009–10 से जुलाई 2012 के बीच फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के गोदामों में नष्ट हो गया।[45] पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 2.5 लाख पंचायत घर बनाने में बहुत धन लगाया है और इन सब स्थानों पर कंप्यूटर भी लगाया गया है तथा सब जगह सौर ऊर्जा की व्यवस्था भी की गई है। यह बात थोड़ी अटपटी नहीं लग रही है कि सरकार के पास पंचायत घर बनाने के लिए तो पैसे हैं लेकिन उसके पास पूरे देश में खाद्यान्न–भण्डारगृह बनाने के लिए धन नहीं है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 2004–05 ने बड़े कॉर्पोरेट घरानों और व्यापारियों को 32 लाख करोड़ रूपए बांट दिए करोड़ों में छूट के रूप में। इस श्रेणी को बजट के कागजों में राजस्व त्याग की श्रेणी में रखा जाता है जो 2013–14 में लगभग 5 लाख करोड़ रूपए थी।[46]

भारत के किसानों के मध्य गरीबी और ऋण को एक भयानक कथा के रूप में कहा जाता है। देश में अब तक 1995 से 2005 के मध्य 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। यदि हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो भारत में दुर्घटनाओं में मौत और आत्महत्या किसानों के मध्य सर्वाधिक थी जो 2010 में लगभग 15964 थी।

पिछले 16 वर्षों में यदि हम 1995 से 2012 की बात करें तो जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आत्महत्या से संबंधित आंकड़ा एकत्रित करना प्रारम्भ किया था तब इसकी संख्या 256913 थी। आधुनिक मानव इतिहास में आत्महत्या की इस तरह की घटनाएं बहुत दुखद हैं क्योंकि 135756 किसानों ने 2003–10 के बीच आत्महत्या कर ली। वर्ष 1995 से 2002 के बीच की कुल संख्या 121157 थी। औसतन यदि हम हर वर्ष हुए किसानों के आत्महत्या की बात करें तो 2003 से 2010 के मध्य यह 1825 रही है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है।[47]

---

33 Dreze, J. and Sen, A. (1989), "Hunger and Public Action" (Clarendon, Oxford)
34 http://pib.nic.in/feature/feyr98/fe0798/PIBF2107983.html
35 http://www.thehindu.com/news/national/at-26320-million-tonnes-this-year-foodgrain-production-touches-a-record-high/article5691292.ece
36 Global Hunger Index Report, 2013
37 http://www.ifpri.org/ghi/2013/concept-global-hunger-index
38 Global Hunger Index Report, 2013, p.16
39 http://www.unicef.org/india/children_2356.htm
40 HUNGAMA survey 2011 Report, Accessible at http://hungamaforchange.org/
41 2013 Global Hunger Index, Appendix B, data Underlying the Calculation of the 1990/95, 2000/ 05, and 2013 GHI Scores p 51
42 http://www.livemint.com/Opinion/TTLqU0Cg2iF4hYtJSHtMRI/PDS-a-story-of-changing-states.html
43 http://ibnlive.in.com/news/how-the-pds-is-changing-in-chattisgarh/137153-7.html
44 NSS report 538: Level and Pattern of Consumer Expenditure, Alternatively accessible at Millennium Development Goals, India Country Report 2014, Social, Statistics Division, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India
45 http://timesofindia.indiatimes.com/india/Over-17000-tonnes-of-grains-wasted-in-3-years/articleshow/22056182.cms
46 http://www.rediff.com/news/column/indias-food-crisis-rotting-food-grains-hungry-people/20130401.htm
47 National Crime Record Bureau (NCRB) Data, also available at http://www.thehindu.com/multimedia/archive/00820/Farm_Suicides__All__820602a.pdf

VI अनैतिक इरादे

"उपहार उस वस्तु में नहीं निहित होता जो दी जाती है अपितु दाता के भावना में निहित होता है।" [48]

ऐसा नहीं है कि हमारे देश में गरीबी और असमानता की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन जो सर्वाधिक खतरनाक बात लगती है वह है कि क्यों पिछले 10 वर्षों में जब विकास की गति इतनी तेज थी तब सरकार केवल बड़ी–बड़ी बातें करती रही और इस समस्या के प्रति एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की अपेक्षा अप्रभावी योजनाओं में विश्वास करती रही। भ्रष्टाचार और क्रोनी कैपिटलिज्म ने मिलकर बहुत से विभागो में एक नीतिगत अनिर्णय की स्थित बना दी जिसने विकास को ही रोक दिया। घोटालों की एक लम्बी श्रृंखला जो स्पेक्ट्रम घोटाले से प्रारम्भ होकर कोयला घोटाले तक जाती है और जिसने जन–नीति निर्धारकों की विश्वनीयता और नीयत पर प्रश्नचिन्ह लगाया है, वह भी इस विकास को बाधित करती रही है। हालांकि पारिभाषिक रुप में तो जनतंत्र बच गया लेकिन वास्तिवकता में इसका सारतत्व इस पूरे दशक में अदृश्य नजर आया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जैसी संस्थाओं का प्रयोग एक केन्द्रीय अन्वेषण एजेन्सी के रूप में न होकर राजनैतिक अस्त्र के रूप में हुआ। जिससे इन संस्थाओं काअ धीरे–धीरे पतन हुआ। मई २०१३ में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई विश्वनीयता पर कोयला घोटाले के संदर्भ में प्रश्न किया तथा उस पर तीखा प्रहार किया एवं उसे अपने मालिक के लिए बोलने वाला पिंजरे में बंद तोता कहा और इससे भी दुखद बात यह कही कि तोता तो एक है लेकिन इसके मालिक कई हैं।[49] उच्चतम न्यायलय ने और आगे कहा कि 'सरकार में बैठे अधिकारियों के कहने पर रिपोर्ट का सार तत्व ही बदल दिया गया था।'[50]

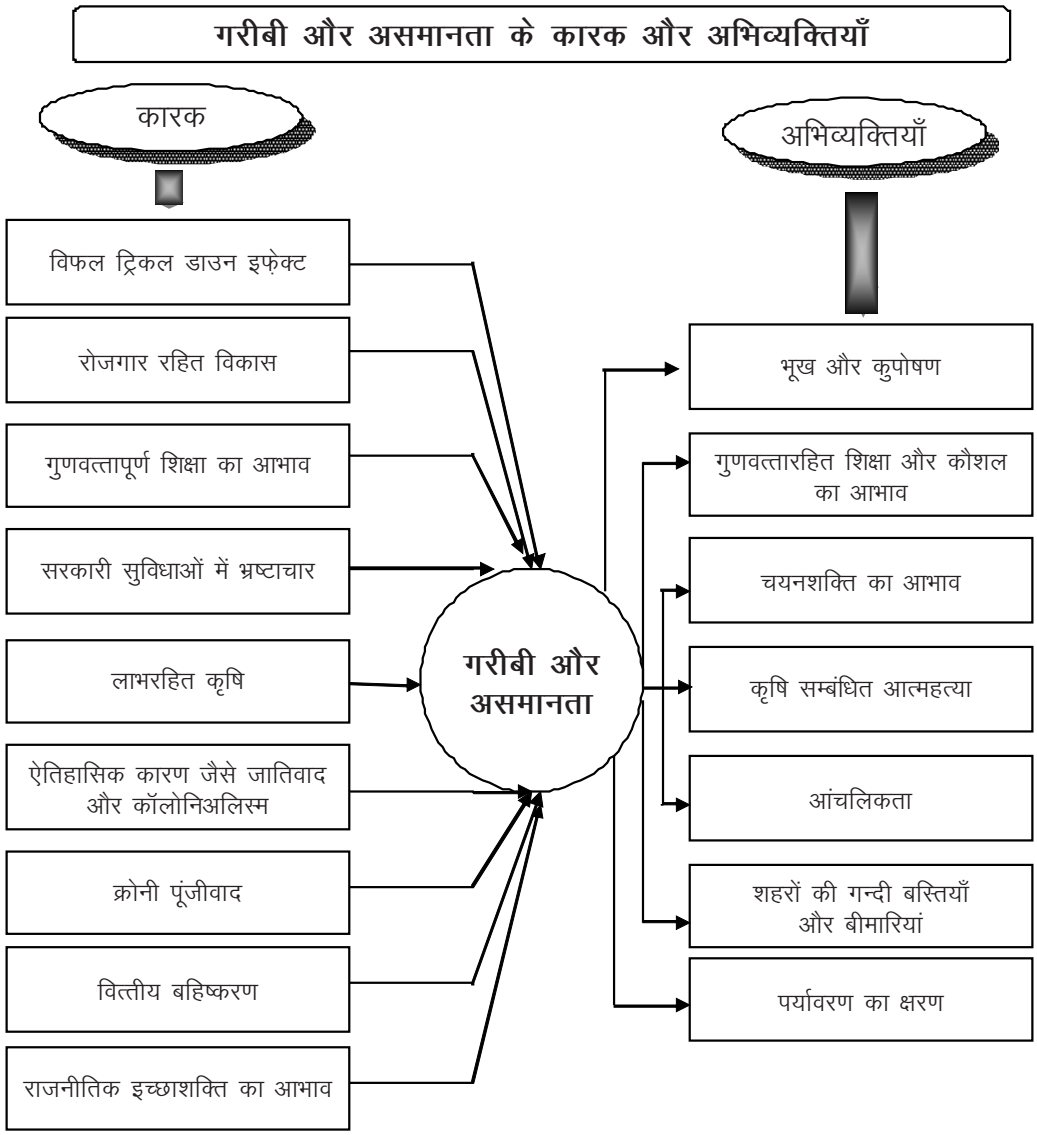

गरीबी और असमानता के कारक और अभिव्यक्तियाँ

इस तरह की बातें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी संस्थाओ की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं। इससे इस तरह के घोटालों में राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी गलत बातों को प्रोत्साहन मिलता है। इन सब बातों से इस विक्षुब्ध वास्तविकता का भी पता चलता है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाओं को राजनीतिक उपयोग के लिए तथा इस तरह की निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है।

जिस तरह सरकार द्वारा लोकपाल के मुद्दे को सम्हाला गया, उससे एक और अनैतिक इरादा सामने आया। जिस प्रकार प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने इस विषय में हस्तक्षेप किया था और इसे संभाला था उसपर यहाँ तक कि नारायण मूर्ति ने एक साक्षात्कार में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी।[51] देश में इस तरह केंद्र सरकार द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार के मामले को लेकर स्थिति यह हो गयी थी कि पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। CNN&IBN ने देश की दशा सर्वेक्षण में जिसे सेन्टर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज द्वारा किया गया था, में स्पष्ट रूप से बताया है कि देश में हर तरफ फैला भ्रष्ठाचार एक विषय बन चुका है विशेष रूप से शिक्षित लोगों के बीच, चाहे गाँव हो अथवा शहर।

इसमें जिन लोगों के बीच सर्वे किया गया था उनमें से 60 प्रतिशत लोगों का मानना है की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार एक बहुत भ्रष्ट सरकार चला रही है जबकि शहरी 66 प्रतिशत लोगों का मानना है की भ्रष्टाचार का स्तर घृणा के स्तर तक पहुंच गया है। कॉलेज में शिक्षा प्राप्त 71 प्रतिशत लोग ऊपर कही बात से सहमति रखते हैं।[52]

भारत भ्रष्टाचार की अनदेखी नहीं कर सकता क्योंकि यह गरीबों को और गरीब बनाता है। दुर्भाग्य से गरीबी और भ्रष्टाचार साथ–साथ चलते हैं जो कि बहुत से लोगों की जिंदगी के लिए खतरा है। यह स्थिति तब और भयानक हो जाती है जब लोगों को स्वास्थ्य और पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं के लिए घूस देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भ्रष्टाचार का प्रभाव बहुत ही विनाशकारी है।

भ्रष्टाचार ने बच्चों से उनकी माँ को छीन लिया, परिवार को स्वास्थ्य सेवाओ से वंचित किया, लोगों को भोजन से वंचित किया, बुजुर्गो की सुरक्षा छीनी और व्यवसाय को पूंजीरहित बना दिया।[53] ट्रांसपरेन्सी इंटरनेशनल ने अपने शोध द्वारा यह स्थापित किया है कि भ्रष्टाचार में कमी का अर्थ मातृ मृत्युदर में कमी, युवाओं की बेहतर शिक्षा और साफ सफाई की बेहतर पहुंच है।

इस बात में कोई विरोधाभास नहीं है कि जबतक देश में मजबूत व्यस्थित सुधार नहीं किया जाता धारणीय और समावेशी विकास के लिए तबतक शानदार भारत (शाइनिंग इंडिया) और बीमार भारत (सफरिंग इंडिया) के बीच अंतर बढ़ता ही रहेगा। लेकिन यह विकास वैसा नहीं होना चाहिए जैसा कि 1991 से हो रहा है। ऊपर जो भी कहा गया है उससे बेहतर परिणाम और कुछ भी नहीं हो सकता है कि "समाज में पूर्ण बराबरी और पूर्ण कुशलता नहीं हो सकती लेकिन लोगों को ये सोचना और निर्णय करना होगा की लोग एक दूसरे के लिए कितना बलिदान कर सकते हैं।"[54]

एक और महत्वपूर्ण हस्तक्षेप जिसकी देश की गरीबीरेखा और न्यूनतम आय के निर्धारण में तुरंत सहायता ली जानी चाहिए तथा यह जीविका पर निश्चित रूप से नहीं आधारित होना चाहिए बल्कि यह सब सशक्तिकरण के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। फरवरी 2014 में प्रकाशित मैकेंजी ग्लोबल इंस्टिट्यूट[55] की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक नई सशक्तिकरण रेखा का प्रस्ताव किया गया है जो आय की असमानता पर अधिक समग्र मापदंड रखेगी।

सशक्तिरण रेखा प्रत्येक घर के न्यूनतम आर्थिक लागत पर विचार करती है जो कि 8 प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है : भोजन, बिजली, आवास, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। इन वस्तुओं से इस बात की गणना की जाती है कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस स्तर के उपभोग की आवश्यकता होगी, मूलभूत ढाँचा और पहुंच के लिये कुशल–लागत को ध्यान मेंरखते हुये। यह रेखा राष्ट्रीय जीवन स्तर पर सबके लिए एक नई सोच प्रदान करती है। यहां पर यह बताना आवश्यक हो जाता है की जो सरकारी गरीबी रेखा है उससे डेढ़ गुना ज्यादा उपभोग की आवश्यकता होती है।

---

48 Seneca, Moral Essays, Volume III: de Beneficiis

49 http://www.thehindu.com/news/national/cbi-urges-supreme-court-to-free-the-agency-from-being-a-caged-parrot/article5391613.ece

50 http://timesofindia.indiatimes.com/india/CBI-a-caged-parrot-heart-of-Coalgate-report-changed-Supreme-Court/articleshow/19952260.cms

51 http://www.ndtv.com/article/india/upa-s-handling-of-lokpal-issue-sad-narayana-murthy-112605

52 http://www.firstpost.com/politics/stench-of-corruption-has-stuck-to-upa-all-india-survey-2-57473.html

53 http://www.huffingtonpost.com/huguette-labelle/to-end-poverty-you-have-t_b_4396930.html

54 http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21597931-up-point-redistributing-income-fight-inequality-can-lift-growth-inequality

55 From Poverty to Empowerment: India's Imperative to Jobs, Growth, and Effective Basic Services, February 2014, McKinsey Global Institute

List of Indians who are Billionaires

INDIA		
GDP: $1.9 Tln		
Population: 1.2 Bln		
Total Net Worth: $191.5 Bln		
World Rank	**Name**	**Net Worth**
40.	मुकेश अंबानी	$18.6 bln
52.	लक्ष्मी मित्तल	$16.7 bln
61	अजीम प्रेमजी	$15.3 bln
82.	दिलीप संघवी	$12.8 bln
102.	शिव नादर	$11.1 bln
191.	कुमार बिरला	$7.0 bln
244.	सुनील मित्तल एंड फैमिली	$5.7 bln
281.	अनील अंबानी	$ 5.0 bln
281.	मिक्की जगतानी	$ 5.0 bln
295	सावित्री जिंदल एंड फैमिली	$ 4.9 bln
295.	सायरस पूनावाला	$ 4.9 bln
295.	शशि और रवि रूईया	$ 4.9 bln
396.	उदय कोटक	$ 3.8 bln
446.	आदि गोदरेज एंड फैमिली	$ 3.5 bln
446.	जमशेद गोदरेज एंड फैमिली	$ 3.5 bln
506.	देशबंधु गुप्ता	$ 3.2 bln
551.	कुशल पाल सिंह	$ 3.0 bln
580.	अनिल अग्रवाल	$ 2.9 bln
609.	गौतम अदानी	$ 2.8 bln
731.	ब्रिजमोहनलाल मुंजा	$ 2.4 bln
731.	पंकज पटेल	$2.4 bln
764.	इंदु जैन	$ 2.3 bln
796.	कलानिथि मारन	$ 2.2 bln
828.	मालविन्द्र एवं शिवेन्द्र सिंह	$ 2.1 bln
931.	सुभाष चन्द्रा	$ 1.9 bln
931.	चन्द्रु रहेजा	$ 1.9 bln
973.	राहुल बजाज	$ 1.85 bln
973.	अजय काल्सी	$ 1.85 bln
988.	राशिद नौरोजी	$ 1.80 bln
988.	रवि पिल्लई	$ 1.80 bln

World Rank	Name	Net Worth
988.	सन्नी वर्की	$ 1.80 bln
988.	एम.ए. युसूफ अली	$ 1.80 bln
1046.	एन.आर. नारायण मूर्ति	$ 1.70 bln
1092.	वेनुगोपाल धूत	$ 1.60 bln
1092.	मंगल प्रभात लोढ़ा	$ 1.60 bln
1143.	बेनुगोपाल बांगर	$ 1.55 bln
1154.	मुरली दीवी	$ 1.50 bln
1154.	सेनापति गोपालकृष्णन एंड फैमिली	$ 1.50 bln
1154.	रवि जापुरिया	$ 1.50 bln
1203.	अजय पारिमल	$ 1.45 bln
1210.	नंदन निलेकणि एंड फैमिली	$ 1.40 bln
1210.	रंजन पाल	$ 1.40 bln
1284.	बाबा कल्यानी	$ 1.30 bln
1356.	अश्विन दानी	$ 1.25 bln
1372.	राकेश झुनझुनवाला	$ 1.20 bln
1372.	नीरव मोदी	$ 1.20 bln
1372.	मोफतराज मुनोत	$ 1.20 bln
1442.	बृज भूषण सिंघल	$ 1.15 bln
1465.	युसूफ हामिद	$ 1.10 bln
1465.	लक्ष्मण दास मित्तल	$ 1.10 bln
1540.	के. दिनेश एंड फैमिली	$ 1.05 bln
1540.	विक्रम लाल	$ 1.05 bln
1565.	हरिन्द्रपाल बंगा	$ 1.00 bln
1565.	टी.एस. कल्याण रमन	$ 1.00 bln
1565.	बी.आर. शेट्टी	$ 1.00 bln
1565.	जीतेन्द्र वीरवाणी	$ 1.00 bln

Source : Forbes India, April 4, 2014 Issue

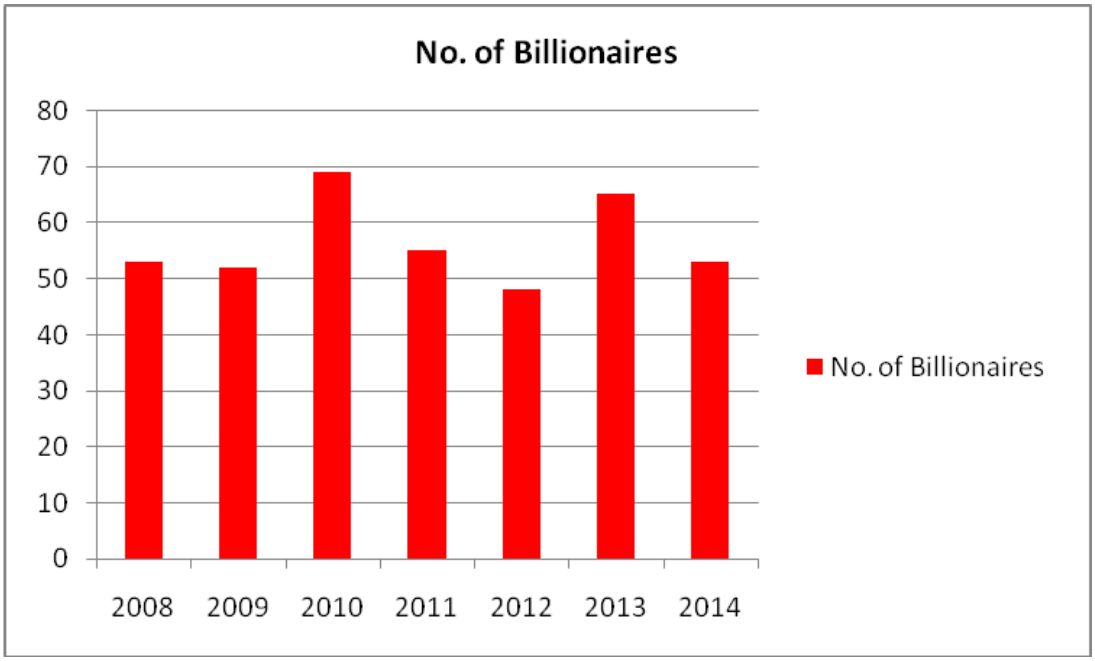

Source : Forbes India, April 4, 2014 Issue

http://theanksden.wordpress.com/2008/03/06/the-indian-billionaires-forbes-2008/

http://forbesindia.com/article/web-special/india-has-52-billionaires;-mukesh-ambani-richest/7192/1

http://www.forbes.com/lists/2010/77/india-rich-10_Indias-Richest_Rank.html

http://www.forbes.com/sites/naazneenkarmali/2011/03/10/the-worlds-billionaires-2011the-india-story/

http://wiseinvestmentideas.blogspot.in/2012/03/48-indian-billionaires-from-forbes-list.html

http://www.forbes.com/india-billionaires/list/

IPF's Publications

1.	Terrorism and Indian Media	80.00
2.	आतंकवाद और भारतीय मीडिया	80.00
3.	Deceptive Equality (Deconstructing the Equal Opportunity Commission)	50.00
4.	भ्रामक समानता (समान अवसर आयोग की समीक्षा)	50.00
5.	Census 2011: Blinkered Vision, Fragmented Ideas	50.00
6.	जनगणना 2011: बाधित दृष्टि विखंडित विचार	50.00
7.	न्यू मीडियाः चुनौतियाँ और संभावनाएँ	50.00
8.	The Issue of Enemy Property and India's National Interest	50.00
9.	राष्ट्रीयता का यक्ष प्रश्न? (शत्रु संपत्ति पर सांप्रदायिक राजनीति)	35.00
10.	अजीज बर्नी की पुस्तक "आरएसएस की साजिश–26/11 (सच या झूठ का पुलिंदा?)	50.00
11.	षड़यंत्र सिद्धांत के खलनायक बेनकाब	50.00
12.	चीनी विस्तारवाद (भारतीय सीमा का अतिक्रमण)	50.00
13.	लोकतंत्र पर प्रहार (नागरिक अधिकारों का हनन)	50.00
14.	सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक (लोकतंत्र, संघवाद, पंथनिरपेक्षता पर प्रहार)	30.00
15.	Hole in the Bucket (Examining Prevention of Communal & Targeted Violence Bill-2011)	30.00
16.	NAC's Hindu Apartheid Law (Prevention of Communal & Targeted Violence Bill-2011)	25.00
17.	The Dragon Tale (Dubious Design, Dangerous Liaison)	60.00
18.	राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाम राष्ट्रीय एकता परिषद (सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक पर टकराव)	20.00
19.	Cross Purposes	80.00
20.	भ्रामक उद्देश्य	80.00
21.	समकालीन समाज में बुद्धिजीवी	30.00
22.	Intellectuals in Contemporary Society	30.00
23.	Assam: Bending Over Backwards (Trespassing Causes Demographic Damage)	30.00
24.	Judiciary, Gender & Uniform Civil Code	50.00
25.	Predicament of Minorities in Pakistan	100.00
26.	पाकिस्तान में अल्पसंख्यक!	80.00
27.	Hindus Betrayed (Religious Cleansing in Bangladesh)	80.00
28.	बांग्लादेश में हिन्दुओं पर संगठित हिंसा	80.00

डॉ. राहुल सिंह बिरला इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (BIMTECH)
ग्रेटर नोएडा (उ.प्र) में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

INDIA
POLICY
FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

D-51, First Floor, Hauz Khas, New Delhi - 110016
Tel.: 91+11-26524018
Fax: 91+11-46089365
E-mail: indiapolicy@gmail.com
Website: indiapolicyfoundation.org

ISBN : 978-81-925223-5-7

9 788192 522357

Price : Rs. 50/-

I'M - 9312431409